

राष्ट्रदूत

जालोर

Rashtradoot

जालोर, गुरुवार 25 सितम्बर, 2025



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा... 75 वर्ष

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर

2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना सहित

राजस्थान को 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए की परमाणु विद्युत, अक्षय ऊर्जा, रेल, सड़क,
पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, स्वास्थ्य एवं अन्य परियोजनाओं का उपहार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

विकास पथ पर
आपणो अग्रणी राजस्थान...

15 हजार युवाओं को

सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण

मुख्य अतिथि

नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर

से नई ट्रेनों की शुरुआत

शिलान्यास

- बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना (8,500 करोड़ रुपए)
- जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें (13,183 करोड़ रुपए)
- राजसमन्द, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, जयपुर, भरतपुर, अलवर जिलों में जल संसाधन में रामजल सेतु परियोजना के 9 कार्य (18,468 करोड़ रुपए)
- बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरु, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं (5,884 करोड़ रुपए)
- भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण तथा 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण (878 करोड़ रुपए)
- बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में 220 केवी के 3 जीएसएस व सम्बन्धित लाइनों के कार्य (348 करोड़ रुपए)

लोकार्पण

- 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं एवं 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी (10710 करोड़ रुपए)
- पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (3,132 करोड़ रुपए)
- ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य (2,365 करोड़ रुपए)
- बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य (1,758 करोड़ रुपए)
- बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस व लाइन निर्माण (142 करोड़ रुपए)
- डीडवाना-कुचामन में सीवरेज एवं झुंझुनूं में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य (226 करोड़ रुपए)
- आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेन्स सेन्टर (140 करोड़ रुपए)
- भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बड़ेड अस्पताल (128 करोड़ रुपए)

गरिमामयी उपस्थिति

हरिभाऊ किसनराव बागडे

माननीय राज्यपाल, राजस्थान

भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

डी.डी. न्यूज़ पर लाइव प्रसारण



गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025 | दोपहर 12:00 बजे | नापला, छोटी सरवन (बांसवाड़ा)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

प्रधानमंत्री आज बाँसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे

जयपुर (कासं), 24 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बांसवाड़ा दौर पर रहेंगे। इस दौरान मोदी, राजस्थान को 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे।

बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के नापला पहुंचे। उन्होंने

■ प्रधानमंत्री जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें ईसरदा के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिला तक फीडर निर्माण, बीसलपुर व ब्रह्मणी बैराज जैसे महत्वपूर्ण जल प्रोजेक्ट शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पेयजल, पार्किंग व्यवस्था तथा जनसभा में आमजन के बैठने की तैयारियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बांसवाड़ा के नापला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी मौजूद थे।

साथ ही पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर सांसद मदन राठौड़, पूर्व नेता

प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता सहित संभागीय व

जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि गुरूवार को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में 42 हजार करोड़ रुपए की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बिहार का मानस बदलाव का है, परिवर्तन निश्चित है’

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में कहा

■ -जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 सितंबर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि बिहार में बदलाव निश्चित है और उन्होंने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया।
पायलट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाने गए टैरिफ और एच-1बी वीजा शुल्क में एकमुश्त बढ़ोतरी जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों नेताओं की दोस्ती भारत के लिए “बहुत मंहगी” साबित हो रही है।
सचिन पायलट ने पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक के बाद

- पायलट ने आयोग से कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा को भारी समर्थन मिला है और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी।
- तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर पायलट ने कहा, समय आने पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
- पायलट ने जीएसटी पर पूछे सवाल के जवाब में कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे, यह गम्बर सिंह टैक्स है, एक गलती को सुधारने में 8 साल लग गए।

आयोजित प्रेस वार्ता में यह बयान दिया। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। सचिन पायलट ने कहा, 2017 से लगातार आठ वर्षों तक कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे “गम्बर सिंह टैक्स”

कहा और गलतियों की ओर इशारा किया। जब मनमोहन सिंह सरकार जीएसटी लाना चाहती थी, तब भाजपा ने इसका विरोध किया और सत्ता में आते ही यू-टर्न ले लिया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

नयी दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को दीपावली पर 78 दिन का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता

■ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

17 फरवरी से होंगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं

नयी दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बुधवार को संभावित तारीख घोषित की। सीबीएसई की ओर से जारी संभावित तारीखों के अनुसार बोर्ड

■ सीबीएसई ने 2026 से होने वाली 10 वीं 12 वीं बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया है कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी से 15 मार्च के बीच बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।

परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं। उन्होंने बताया है कि इन परीक्षाओं में 45 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक मामले में 3 और प्रोबेशनर गिरफ्तार

जयपुर, 24 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए तीन और प्रोबेशनर (ट्रेनी) एसआई को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एसओजी को कुछ सबूत मिले, जिसके आधार पर तीनों को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया और फिर तीनों ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने का आरोप है, एसओजी इस

■ एसओजी को प्राप्त सबूतों के अनुसार, तीनों पर लीक हुए सॉल्व पेपर पढ़कर एसआई भर्ती में चयनित होने का आरोप है।

मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 59 प्रोबेशनर एसआई समेत 130 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परमेश चौधरी (26) निवासी मालियों की ढाणी, ग्राम त्योदा, थाना सांभर, जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में पुलिस लाइन टोंक; मनोहर सिंह (25) निवासी ग्राम सेडीया, थाना करडा, जालोर, वर्तमान में पुलिस लाइन कोटा शहर, और मनोहर लाल (26) निवासी वियो का गोल्या, ग्राम पुआसा, थाना भीनमाल, जालोर, वर्तमान में पुलिस लाइन सिरौही में तैनात को गिरफ्तार किया है।

एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि अनुसंधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मल्लिकार्जुन खड़गे दो साल के शासन के बाद ही थके-थके क्यों हैं?

वे पुराने बुर्जुग नेताओं, जैसे अंबिका सोनी, मीरा कुमार आदि की विदाई नहीं कर पाये, सीडब्ल्यूसी से और न ही गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला, चरणजीत सिंह चन्नी को शिफ्ट कर पाये

■ -जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 सितम्बर। भले ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 88वें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस पर लंबे समय से नजर रखने वाले एक पर्यवेक्षक का कहना है कि यह पार्टी अभी भी अनिश्चित भविष्य, निष्क्रियता और कई राज्यों में आंतरिक खींचतान से जूझ रही है - हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर असम, केरल और बंगाल तक, जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पिछले छह महीनों से भी अधिक समय से कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें खड़गे और गांधी परिवार शामिल हैं, कांग्रेस कार्य समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) के कुछ उम्मीदवार सदस्यों को हटाकर नए नेताओं को जगह देने में विफल रहे हैं। इन नए नेताओं में शामिल हैं: रजनी पाटिल (हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की प्रभारी), बी.के. हरिप्रसाद (हरियाणा), हरीश चौधरी (मध्य प्रदेश), गिरीश चोडनकर (तमिलनाडु और पुडुचेरी), अजय कुमार लल्लू (ओडिशा), के. राजू (झारखंड), मीनाक्षी नटराजन (तेलंगाना), सप्तगिरी शंकर उलक (मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड), और कृष्ण

■ एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार के सीडब्ल्यूसी में बने रहने का कारण हैं, सोनिया गांधी से नजदीकी। गोगोई, सुरजेवाला व चन्नी अपने-अपने प्रदेश में कांग्रेस के मु.मंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। अतः उन्हें भी सीडब्ल्यूसी से हटाकर, उनका महत्व कम करने का कोई मतलब नहीं निकलता।

■ खड़गे की टीम, रजनी पटेल, हरिप्रसन्न, हरीश चौधरी, गिरीश चौडनकर, अजय कुमार लालू, के.राजू, मीनाक्षी नटराजन, सप्तगिरी और कृष्णा अल्लूवारु, अभी पूर्ण महत्व नहीं पा सके।

■ इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस की सभी प्रांतीय इकाईयों में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं लेती और बाकायदा बरकरार है।

■ और यह ही कारण है कि राहुल गांधी की 1,300 किलोमीटर “वोट अधिकार यात्रा” काफी सफल रही, पर अंतर्कलह के कारण सफलता को वोटों में तब्दील करना मुश्किल हैं।

अल्लवारु (बिहार)।

सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले ए. के. एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार और कुछ अन्य अब भी बने हुए हैं और गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला और चरणजीत सिंह चन्नी को हटाने की कोशिशें भी आंतरिक समीकरणों के चलते सफल नहीं हो पाईं। गौरव गोगोई असम में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं,

जबकि सुरजेवाला और चन्नी क्रमशः हरियाणा और पंजाब में पार्टी की कमान संभालना चाहते हैं।

कांग्रेस के संविधान के अनुसार, एआईसीसी के महासचिवों का सीडब्ल्यूसी सदस्य होना आवश्यक है। जब तक उन्हें सीडब्ल्यूसी में नहीं लिया जाता, तब तक उन्हें “प्रभारी” की उपाधि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एस.आई. भर्ती रद्द करने पर अंतरिम रोक हटाई

शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा कि, “राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ 3 माह में इस मामले की सुनवाई कर दायर अपीलों का निस्तारण करे”

■ -यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 24 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 859 पदों की एस.आई. भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराने की छूट दी गई थी। शीर्ष अदालत ने, हाईकोर्ट की खंडपीठ को कहा है कि वह इस मामले में दायर अपीलों का निपटारा 3 महीने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश बुधवार को कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर

- हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की छूट देने के आदेश पर भी रोक लगाई।
- ज्ञात रहे कि एकलपीठ ने एस.आई.भर्ती पेपरलीक मामले में एस.आई.टी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 28 अगस्त को इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए थे।
- इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट था कि आर.पी.एस.सी. के सदस्य स्वयं पेपरलीक में लिप्त थे और उन्होंने अपने पुत्र-पुत्री समेत कई लोगों को पेपर मुहैया करवाया था।

अपील में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शकधर और उनके सहायक अधिवक्ता हरिंदर नील पैरवी के लिए उपस्थित हुए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर ने

सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग कराने की छूट दी है। जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एस.आई. को स्वतंत्र

निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एकलपीठ ने पेपरलीक की जांच के संबंध में गठित एस.आई.टी. रिपोर्ट का गंभीरता से विश्लेषण कर परीक्षा रद्द करने और आर.पी.एस.सी. अधिकारियों को 2021 में जारी विज्ञप्ति के आधार पर पुनः परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि, यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और मामले की जांच में स्पष्ट हुआ है कि एस.आई. भर्ती परीक्षा के पेपरलीक में स्वयं आर.पी.एस.सी. के सदस्य लिप्त थे। इन्हें आरपीएससी सदस्यों के पुत्र-पुत्री को प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाए गए थे, इन्होंने पेपर्स को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव 24 अक्टूबर को

नयी दिल्ली, 24 सितम्बर। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से चार तथा पंजाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह

■ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की चार तथा पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए 13 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा।

जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में छह अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

का विकल्प बताकर प्रचार कर रही है। उन भारतीयों के लिए, जो आसानी से स्थानीय निवास (परमानेंट रेजिडेंसी/पी.आर.)

और परिवार की स्थिरता चाहते हैं, केनडा सबसे आकर्षक नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया अब भी उन मिड-

के अनुकूल” देश की बना चुका है और अमेरिकी नीतिगत कदमों के बाद से भर्ती एजेंसियां केनडा को एच -1 बी



भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा...75 वर्ष

विकास के नए शिखर पर राजस्थान

₹1,22,000 करोड़ से अधिक की

परमाणु, अक्षय ऊर्जा, बिजली, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी
परियोजनाओं का उपहार

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री
के द्वारा



गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025



13:00 बजे



बाँसवाड़ा, राजस्थान

केन्द्र सरकार की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं

शिलान्यास



अश्विनी माही बाँसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना
1-4 (4x700 MW)



590 MW एफडीआरई परियोजना (1560 MWp सौर
तथा 2500 MWh बीईएसएस), बीकानेर (अवाड़ा)



पावरग्रिड की तीन पारेषण योजनाएँ, राजस्थान से मध्य प्रदेश,
हरियाणा और पंजाब तक 15.5 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु



300 MW सौर पीवी परियोजना, रामगिरि, आंध्र प्रदेश (सेकी)

उद्घाटन



925 MW नोख सौर पार्क, फलोदी, राजस्थान (आरएसडीसीएल)



400 MW सौर पावर परियोजना (जेएसडब्ल्यू एनर्जी)



300 MW सौर परियोजना (ईडन रिन्यूएबल्स)



200 MW सौर परियोजना (सनफ्री एनर्जी)



200 MW सौर परियोजना, बडनू, राजस्थान (अवाड़ा)



300 MW सौर परियोजना (एसीएमई सोलर)



पीएम-कुसुम घटक-सी (फीडर स्तर सोलराइजेशन) के अंतर्गत
विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र - राजस्थान (895 MW),
महाराष्ट्र (2458 MW), मध्य प्रदेश (99 MW), कर्नाटक (65 MW)

राजस्थान सरकार की विकास परियोजनाएं



जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा,
स्थानीय स्वायत्त शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, तथा चिकित्सा
शिक्षा विभाग से संबंधित 31 कार्यों का शिलान्यास एवं 17 कार्यों का उद्घाटन



15,000 युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण

हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ



बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन



जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन



उदयपुर सिटी - चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन

परियोजना के लाभ

लोगों और उद्योगों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन
जीवन को बेहतर बनाने और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हरित ऊर्जा की उपलब्धता

कृषि के लिए किफायती, विश्वसनीय और सतत सिंचाई ऊर्जा हुई सुनिश्चित

लोगों, स्थानीय व्यवसायों, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों के लिए बेहतर रेल संपर्क

आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राजस्थान राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर

स्थानीय समुदायों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन

गरिमामयी उपस्थिति

श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े
राज्यपाल, राजस्थान

श्री भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री मनोहर लाल
केंद्रीय आवासन और शहरी
कार्य एवं विद्युत मंत्री

श्री प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण; तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण,
जन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान
(स्वतंत्र प्रभार) और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन
परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग

श्री अर्जुन राम मेघवाल
केन्द्रीय, कानून एवं न्याय
(स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

श्री भागीरथ चौधरी
केंद्रीय कृषि एवं
किसान कल्याण राज्य मंत्री

श्रीमती दिया कुमारी
उप मुख्यमंत्री, राजस्थान

डॉ. प्रेमचन्द बैरवा
उप मुख्यमंत्री, राजस्थान

इस कार्यक्रम को लाइव देखें



लेह में भारी हिंसा, भाजपा कार्यालय को आग लगाई, चार की मौत, कई घायल

लेह, 24 सितंबर। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार, भाजपा दफ्तर में आगजनी की गई। हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू कर दी गई है। एक साथ पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। बिना इजाजत के जुलूस या प्रदर्शन पर भी पाबंदी है। वहीं, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह शहर में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा की है, उपराज्यपाल ने दुखद मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र

- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन के हिंसक रूप लेने के खिलाफ विख्यात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 15 दिन की भूख हड़ताल वापस ले ली।
- हिंसा तब भड़की जब सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे दो लोगों की तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

स्वस्थ होने की भी कामना की। एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और भाजपा कार्यालय और कई वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को फायरिंग

करनी पड़ी। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण रास्ते का प्रयास विफल हुआ है। लद्दाख की हालात को स्थिर करने

के लिए सीआरपीएफ की चार कंपनियों (कुल मिलाकर 4 सौ जवान मौजूद हैं) को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया। इससे पहले सीआरपीएफ की सात कंपनियां लद्दाख में पहले से ही तैनात हैं जिसमें कुल मिलाकर 700 जवान हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद बुधवार को प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डॉक ने निषेधाज्ञा आदेश जारी कर कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन होने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आकर्षक है ,खासकर उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने को तैयार हैं। जर्मनी के नए “ऑपच्युनिटी/चांसनकार्ट” कदमों का उद्देश्य कुशल पेशेवरों को, तत्काल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के बिना भी अवसर देना है। जो तकनीकी प्रतिभाएं सामाजिक सुरक्षा, रिसर्च लिंग और यूरोपीय बाजारों की निकटता को महत्व देती हैं, उनके लिए जर्मनी (और पूरा यूरोपीय संघ) भरोसेमंद विकल्प है, हालाँकि गैर-अंग्रेजी वर्कप्लेस और कागजी प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं।

ब्रेकिंगट के बाद ब्रिटेन ने ग्लोबल टैलेंट रूट जैसे वीजा और विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर नियमों में ढील देकर प्रतिभाओं को लुभाने की कोशिश की है। लंदन के वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन स्किलड वर्कर लिस्ट और वेतन सीमा में हाल के बदलावों से अनिश्चितता बढ़ी है। इसलिए

नुकसान होगा। सबसे ज्यादा असर जूनियर पेशेवरों, छोटे-मझोले उद्यमों और स्टार्टअप्स पर पड़ेगा जो कम वेतन पर वैश्विक भर्ती करते हैं।कैनडा, यूरोप के कुछ हिस्से और खाड़ी देश शुरूआती से मिड-करियर भारतीयों को सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगे, जबकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया मिड से सीनियर प्रतिभा को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर दूसरे देश आसान या त्वरित रैंजिडैंसी की पेशकश करते हैं तो भारत से युवा कोडरों और मिड-करियर विशेषज्ञों का पलायन हो सकता है। एच-1 बी पर निर्भर एम्प्लॉयर्स को या तो वेतन में बड़ा इजाफ़ा करना होगा, भर्ती रणनीतियाँ बदलनी होंगी (जैसे अमेरिका में स्थानीय टीम बनाना) या भर्ती के भौगोलिक विकल्प बढ़ाने होंगे। उम्मीदवारों के लिए अब वेतन और दीर्घकालिक सुरक्षा के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा: कैनडा और ऑस्ट्रेलिया स्थायी निवास का साफ रास्ता देते हैं, यूरोप जीवनशैली और सामाजिक लाभ देता है, जबकि सिंगापुर और यूएई ऊँची आय और भारत की नज़दीकी का फायदा देते हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे दो साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दी जाती है, न कि पूर्णकालिक महासचिव की। एक बार सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बाद वे आधिकारिक महासचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। एके एंटनी और अंबिका सोनी को हटाने की कोशिश मुख्यतः उग्र कारक से प्रेरित मानी जा रही है। एंटनी (84 वर्ष) 2022 से ही राजनीति से दूर हैं, जबकि 82 वर्षीय अंबिका सोनी अब भी सक्रिय हैं। एंटनी को अपने बेटे अनिल के भाजपा में शामिल होने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अंबिका सोनी का प्रभाव सोनिया गांधी की कृपा से लंबे समय तक रहा है। उनके दौर (1998-2022) में कई नेता उन्हें ‘सोनिया माइनस ए’ कहा करते थे। उनके कई समर्थक भी थे जैसे कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा और पवन बंसल आदि। चुनावी राज्य बिहार कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है, जहाँ राहुल गांधी ने 1300 किलोमीटर लंबी ‘वोट अधिकार यात्रा’ निकाली। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव जैसे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने बड़ी भीड़ खींची और अच्छी भाषण शैली से अपने विरोधियों को भी प्रभावित किया। हालाँकि, कांग्रेस के आंतरिक

मूल्यांकन से पता चलता है कि यह यात्रा वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के सूत्र मानते हैं कि यह अभियान दिखावे में तो जोरदार था, लेकिन मुद्दों पर कमजोर रहा। वोटिंग अधिकार का मुद्दा भी विरोधाभासी रहा - जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वे संतुष्ट हैं, और जिनका नाम गायब है, वे वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए चुनाव में उनका असर सीमित रहेगा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर और असंगठित है, जिससे प्रभावी जनसंपर्क मुश्किल है। इसके अलावा, कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करने से और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तेजस्वी मानते हैं कि वे महागठबंधन के स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी ‘वोट अधिकार यात्रा’ के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से सीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे।

17 फरवरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सकते हैं। परीक्षा देश के अलावा अन्य 26 अन्य देशों में भी आयोजित की जायेगी।उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हर विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और इसके 12 दिनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, अगर 12वीं की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी तो मूल्यांकन 3 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सामने आया कि तीनों आरोपियों ने पेपर लीक माफिया के जरिए परीक्षा से पहले सॉल्वड पेपर हासिल किया था। फिर उसे पढ़कर लिखित परीक्षा पास की। परमेश चौधरी ने मेरिट में 180 वीं., मनोहर सिंह जाट ने 38वीं और मनोहर लाल विस्नोई ने 171वीं रैंक हासिल कर एसआई भर्ती में नियुक्ति हासिल की।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पढ़कर वे लिखित परीक्षा में ना सिर्फ उत्तीर्ण हुए, बल्कि इंटरव्यू में भी आर.पी.एस.सी. सदस्यों की मिलीभगत से अच्छे अंक ला पाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस मामले की जांच में हर सप्ताह पेपरलीक के आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब तक 77 हो चुकी है। आज सुनवाई के दौरान भी 3 ट्रेनी एस.आई. पकड़े गए हैं। ऐसे में अगर एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए तो इससे आमजन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर एस.आई. भर्ती को रद्द करने योग्य माना था, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रामाणित माना है।

इसके जवाब में राज्य सरकार के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए, लेकिन उनकी फील्ड ट्रेनिंग को जारी रखा जा सकता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट की खंडपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। वहीं हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील का निस्तारण करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्तमान में एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक हटी है, ऐसे में राज्यसरकार के पास भी विकल्प बचता है कि वह चाहे तो एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए आर.पी.एस.सी. से पुनः पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार इन्हीं पदों पर दुबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 28 अगस्त वाले भर्ती रद्द करने के फैसले पर 8 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही एस.आई. भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग देने पर पूर्व में लगी हुई रोक को बरकरार रखा था।

लागत वाली माहि-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के गांवों में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 63,683 करोड़ रुपए की स्वच्छ ऊर्जा एवं ट्रांसमिशन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 491 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में 220 केवी के 4 जीएसएस का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें ईसरदा से जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों तक फीडर निर्माण,

राज्यसभा की 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जायेगी और उम्मीदवार द्वारा 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग ने बताया कि राज्य सभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया के तहत 24 अक्टूबर को इन सभी पांच सीटों के लिए सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया जाएगा।

बीसलपुर और ब्राह्मणी बैराज जैसे महत्वपूर्ण जल प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री 2636 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के 11 जिलों में 5884 करोड़ की लागत से पेयजल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। भरतपुर में 128 करोड़ की लागत से 250 बेड के अस्पताल, जयपुर में 140 करोड़ की लागत से आईटी डवलपमेंट सेंटर, और मकरानाब मंडावा में 226 करोड़ की सीवरेज व जलप्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

‘बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार लाने में आठ साल लग गए, और अब सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर आर्थिक सुधार पर भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जो रख अपनाया, सत्ता में आने पर उसका उल्टा रख लिया। पायलट ने कहा कि बिहार में हाल ही में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और राज्य में बदलाव का स्पष्ट माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सभी पार्टियाँ एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ रही हैं। पायलट ने कहा, अमेरिका भारत पर आर्थिक हमला कर रहा है और हम उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीएम मोदी और ट्रंप की मित्रता देश के लिए बहुत भारी पड़ रही है। सचिन पायलट ने जाति जनगणना पर कहा कि सरकार को जातिगत जनगणना को महज औपचारिकता न बनाकर उसे इस तरह कराना चाहिए जिससे वास्तविक सामाजिक भागीदारी का चित्र सामने आए। सिर्फ जनगणना के कॉलम में जाति जोड़ने से काम नहीं चलेगा। पायलटन ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए “वोट चोरी” के मुद्दों पर जाँच शुरू करने के बजाय आयोग उनसे शपथ पत्र माँग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, तो जवाब भाजपा की तरफ से आता है। उन्होंने दोहराया कि बिहार चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब पायलट से पूछा गया कि कांग्रेस अभी तक राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा, सभी निर्णय सही समय पर लिए जाएंगे।

रेल कर्मचारियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रिमंडल ने 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पात्र रेल कर्मचारियों को उत्पादकता-आधारित बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।



MARUTI SUZUKI ARENA

त्योहारों की खुशी अब हुई और बड़ी

GST लाभ और सीमित अवधि फैस्टिव ऑफ़र्स के साथ

30 सितंबर, 2025 तक मान्य

MODEL	S-PRESSO	ALTO K10	CELERIO	WAGONR	SWIFT	DZIRE	BREZZA	ERTIGA	EECO
REDUCTION IN PRICE* (₹) UP TO	129 600	107 600	94 100	79 600	84 600	87 700	112 700	46 400	68 000
NOW STARTING AT* (₹)	349 900	369 900	469 900	498 900	578 900	625 600	825 900	880 000	518 100
ADDITIONAL FESTIVE OFFERS* (₹) UP TO	60 000	70 000	65 000	75 000	70 000	5 000	56 000	7 500	45 000

BOOK NOW

UP TO 100% PROCESSING FEE WAIVER ON CAR FINANCE*





T&C available at dealership. Features/accessories vary by variant. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. *Offers / Prices differ by variant/model/location/city and may change or end without notice. Includes consumer, exchange, and institutional/rural offers (where applicable) on select models. Offer values shown are maximums. Prices subject to GST rates as notified by the Government. *Reductions and starting prices vary by variant. *Valid with select financiers, for personal-use vehicles only.



SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at
1800-102-1800



राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2006/17286** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायन हाऊस, अन्नपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नैत रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908